

प्रति अंक मूल्य - 4/-रु.

वार्षिक चन्दा 100/- रु. मात्र

आजीवन सदस्यता शुल्क : 700/-

प्रकाशन तिथि/पोस्टिंग तिथि : 01-16 अगस्त 2020

अनसूया

आद्य-संपादक : ज्योत्सना मिलन
संपादक : प्रीति शान्त

वर्ष : 35 अंक : 19 अगस्त 2020

पहले कोरोना की मार अब बारिश ने मचाया हाहाकार

कोरोना और लॉकडाउन ने मजदूरों की बेहद दयनीय स्थिति को उजागर किया है। फिर चाहे वे प्रवासी मजदूर हों या अपने ही गाँव-शहर में काम करने वाले मजदूर। सभी लोगों के जीवन को इस आपदा ने बुरी तरह से प्रभावित किया है। लगभग दो महीने के लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश करते इन मजदूरों पर प्रकृति की भी मार पड़ी। इन दिनों मूसलाधार बारिश के कारण काम के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मजदूर अपने-अपने घरों में भूखे-प्यासे बैठे हैं। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और वे बेबस हैं।

जब बारिश हल्की होती या कम होती तो भाई-बहन टोकरी लेकर फेरी पर निकल जाते। दिहाड़ी मजदूरों को

अभी बहुत कम काम मिल पा रहा है।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिहार बाढ़ का प्रकोप झेल रहा है। कटिहार जिले में बाढ़ का रूप भयंकर हो जाता है जिसमें कई घर डूब जाते हैं। गाय-भैंस के साथ दिन गुजारने पड़ते हैं। कई बार स्कूलों में शरण लेते हैं। शहर में पानी निकासी का ठीक प्रबंधन नहीं होने के कारण हर साल इसे बाढ़ से जूझना होता है। उचित कार्य योजना के अभाव में जनसाधारण को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर साल वही कहानी दोहराई जाती है, बाढ़ आती है, हल्ला मचता है, दौरे किये जाते हैं और फिर राहत पैकेज की घोषणाएँ की जाती हैं। लेकिन ऐसी आपदा दोबारा न आए इसके लिए कोई नहीं सोचता।

किसानों की सारी मेहनत पानी में

कोविड-19 और बाढ़

भीतर

3. फिलहाल गाँव में ही काम करेंगे ...
5. यह समय किसी को भी दोषी ...
7. काम तो मिल रहा है लेकिन वह...
9. बहनों को सरकारी योजनाओं से...



बह जाती है वे कर्ज में डूब जाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाली बहनों की सारी मिट्टी बह जाती है। **मिट्टी से बने बरतन फिर से मिट्टी बन जाते हैं और पीछे छूट जाती है भूख, बेबसी, परेशानी।** जो बहनें पत्तों से थाली, कटोरी बनाती हैं उनकी भी मेहनत खराब हो जाती है क्योंकि पानी में सभी पत्तों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। ये लोग रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाले लोग हैं जो अब तक कोरोना की मार से जूझ रहे थे और अब बारिश ने उनके जीवन में हाहाकार मचा दिया है।

यह भी जैसे कम हो कि एक बार फिर से मुँगेर में लॉकडाउन लगा दिया गया। छोटी-छोटी दुकानवाले अभी अपनी दुकानें खोलने के बारे में सोच ही रहे थे कि फिर से होने वाले लॉकडाउन ने उनकी आस को खत्म कर दिया। कई लोगों की जमा-पूँजी खत्म हो गई है। रोज़गार तो क्या अपना घर चलाने के लिए भी महाजन से कर्ज लेना पड़ा था। अब वही महाजन घर के दरवाजे बजाने जब-तब आ जाते हैं।

इन लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है लेकिन भूख तो रोज़ लगती है। पिछले दिनों सरकार ने घोषणा की कि सभी को निःशुल्क राशन दिया जाएगा लेकिन केवल चावल-आटे और थोड़ी-सी दाल से तो जीवन निर्वाह नहीं हो सकता।

घरेलू कामगार बहनों में से कुछ ने वापस अपने काम पर जाना शुरू किया। ये सभी बहनें अत्यधिक सावधानी बरतती हैं लेकिन पिछले दिनों कोरोना का संक्रमण कुछ ज्यादा बढ़ जाने के कारण मालिक लोग इन बहनों को अपने घर में काम करवाने में हिचकने लगे। कुछ ने तो बहनों को काम पर आने से सीधे ही मना कर दिया। इनका काम लॉकडाउन के समय बिलकुल बंद हो गया था इसलिए इनमें से अधिकतर ने अपने घर के खर्चों की पूर्ति के लिए महाजन से पैसा उधार लिया था यह सोचकर कि काम फिर से शुरू होगा तो चुका देंगे मगर अब वे सब बहनें यह सोच-सोचकर परेशान हैं कि कर्ज को कैसे चुकाएँगी?

सबसे ज्यादा प्रभाव निर्माण कामगार, खेत मजदूर,



किसान बहनों, सब्जी-भाजी बेचने वाली बहनों पर पड़ा है। लॉकडाउन की अनिश्चितता, कोरोना का बढ़ता संक्रमण निर्माण काम को शुरू ही नहीं होने दे रहा है इसलिए निर्माण कामगार बेरोज़गार होकर घर में बैठे हैं। किसान भाई-बहन भी बहुत मुसीबत में हैं क्योंकि मक्का पक रहा है उस पर पानी पड़ गया। फसल भीग जाने के कारण दाम ठीक नहीं मिलेंगे। दूसरी फसल की तैयारी करनी थी वह भी नहीं हो पाई। खेतों में काम नहीं है इसलिए खेत मजदूर बेकार बैठे हैं। लोगों को एकत्रित होने से रोकने के लिए अब कटाई, छंटाई और खेती के बहुत सारे कामों में तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है।

जो बहनें सिलाई काम करती थीं या ब्यूटीपार्लर चलाती थीं, उनका काम ठप्प हो गया है। न सिलाई के लिए कपड़ा आता है न कोरोना का डर किसी को ब्यूटीपार्लर में आने देता है। जब तक मानसून रहेगा तब तक निर्माण का काम नहीं हो पाएगा। ईंट-भट्टे का काम भी बंद पड़ा है।

अगर यही हाल रहा तो आगे चलकर मजदूरों का छंटनी हो जायेगी। अपने गाँव-शहर में काम नहीं मिलेगा तो उन्हें मजबूरी में पलायन करना होगा। इसलिए अब सभी चाहते हैं कि इसके बाद यह लॉकडाउन आगे न बढ़े और सभी लोगों को काम मिलना शुरू हो जाए।

-अंजना बेन,
ऑर्गनाइजर

अनसूया के सभी पाठक-मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

फिलहाल गाँव में ही काम करेंगे

को विड-19 के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। गरीब-अमीर, हर किसी पर इस महामारी का असर पड़ा है। सभी इस भयानक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं फर्क बस इतना है कि जिनके पास पैसा है, सेविंग है उन्हें इस लॉकडाउन की वजह से ज्यादा परेशानी नहीं हुई लेकिन हमारी श्रमजीवी बहनें जिन्हें दो समय का भोजन जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उनके लिए इस महामारी ने मुश्किलें और बढ़ा दीं। यों भी इनके पास निश्चित रोजगार नहीं रहता है।

‘सेवा’ म.प्र. वर्तमान में 5 लाख सदस्यों के साथ काम कर रही है। इनमें से 1,49,089 सदस्य ग्रामीण हैं। ये ग्रामीण सदस्य बहनें खेती बाड़ी, निर्माण श्रमिक व अन्य व्यवसाय से जुड़ी हैं। गाँव में रहनेवाली कई आदिवासी सदस्य बहनें काम नहीं मिलने पर पूरे परिवार के साथ गाँव से शहरों की ओर काम की तलाश में पलायन करती हैं और कई बार तो इन शहरों से दूसरे राज्यों में भी चले जाते हैं। कुछ बहनों के पति, भाई, पिताजी व परिवार के अन्य सदस्य काम करने के लिए दूसरे शहरों जाते हैं और समय-समय पर गाँव में आते हैं।

कोविड-19 का भयावह प्रभाव पड़ना शुरू हुआ तब भी कई प्रवासी भाई-बहन दूसरे जिलों व राज्यों में काम कर रहे थे। अचानक से लॉकडाउन लगने पर कुछ दिनों तक तो जो जहाँ था, वहीं अटक गया। लेकिन जैसे- जैसे समय बीतता गया इन श्रमिकों की स्थिति खराब होती गई क्योंकि न इनके पास पैसा था और ना ही ये परिवार को किसी तरह की मदद भेज पा रहे थे, मतलब दोनों जगह

की स्थिति बिगड़ती गई।

हालाँकि, सरकार द्वारा इनको भोजन के पैकेट, रहने की सुविधा दी गई परन्तु ये पर्याप्त नहीं था। परेशान होकर कुछ श्रमिक भाई-बहन पैदल, साइकिल यानी जिसको जैसी सुविधा मिली उसके अनुसार अपने घर के लिए वापस चल दिए। कुछ समय बाद सरकार द्वारा इन श्रमिकों के लिए बस, ट्रेन भी चलाई गई ताकि सभी प्रवासी श्रमिक अपने-अपने घरों तक पहुँच पाएँ।

हमारे सदस्य भी अपने गाँव वापस आने लगे। ‘सेवा’ द्वारा निगरानी समिति एवं सूचना केंद्र व आगोवानों की मदद से इन श्रमिकों की सूची स्थानीय स्तर पर तैयार की गई। इन्हें पंचायत, आंगनवाड़ी के सहयोग से गाँव के बाहर ही 14 दिन क्वारेंटाइन करने में सहायता की गई। इन्हें पंचायत, गाँव के माध्यम से दो समय का भोजन उपलब्ध करवाया गया। सबका कोरोना टेस्ट करवाया गया, उसके बाद वे सब अपने-अपने घर गए।

ये सभी श्रमिक घर तो वापस आ गए परन्तु इनके पास काम नहीं था। तब कार्यकर्ता, निगरानी समिति व सूचना केंद्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई कि मनरेगा में कौन से श्रमिक काम करेंगे, किसके पास जॉबकार्ड है या किसके पास नहीं है, राशन कार्ड है या नहीं- इसकी सूची बनाई गई।

जिनके पास जॉबकार्ड थे, उनको मनरेगा के तहत काम दिलवाने के लिए पंचायत में सारे आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करवाया। जिनके पास जॉबकार्ड नहीं हैं, उनके लिए आवेदन करवाए गए। जब सभी के कार्ड बन गए तो उनको भी काम दिलवाया गया।

जिनके पास जॉबकार्ड थे, उनको मनरेगा के तहत काम दिलवाने के लिए पंचायत में सारे आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करवाया। जिनके पास जॉबकार्ड नहीं हैं, उनके लिए आवेदन करवाए गए। जब सभी के कार्ड बन गए तो उनको भी काम दिलवाया गया। इस तरह पिछले दो माह में 19,720 श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम दिलवाया गया और वर्तमान में भी यह कार्य चल रहा है। प्रवासी श्रमिकों के पास राशन कार्ड नहीं होने पर पंचायत व जनपद पंचायत में समन्वय करके सभी को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन दिलवाया गया।

इस तरह पिछले दो माह में 19,720 श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम दिलवाया गया और वर्तमान में भी यह कार्य चल रहा है। प्रवासी श्रमिकों के पास राशन कार्ड नहीं होने पर पंचायत व जनपद पंचायत में समन्वय करके सभी को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन दिलवाया गया।

छतरपुर जिले के नौगांव की सुमनरानी बताती हैं कि उनके पति और बड़ा बेटा लॉकडाउन के समय दिल्ली में फँस गए। यहाँ वे अपनी बहू और दो पोतों के साथ रहती हैं। बहू सिलाई करती है और बच्चे समय में खेती का काम करती है। सुमन बेन भी खेतों में काम करती हैं। उनके पास थोड़ी-सी जमीन है जहाँ वे गेहूँ लगाते हैं जो उनके घर में लग जाता है। उनके पोते सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं।

जब इस बीमारी के फैलने का पता चला तो सुमनबेन बहुत परेशान हो गईं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में जब उनके परिवार के लोग दिल्ली में फँसे हैं, वे क्या करें। पति और बेटे से रोज़ फोन पर बात तो हो जाती थी लेकिन उनके लिए इतना पर्याप्त नहीं था। वे चाहती थीं कि वे लोग जल्दी से वापस आ जाएँ।

इस बीच खेतों में काम बंद हो गया। धीरे-धीरे घर का सारा सामान भी खत्म होने लगा। किसी तरह उनके पति और बेटा अपने घर पहुँचे। उनकी हालत काफी खराब थी क्योंकि कई दिनों से उन्हें न पेट भर भोजन मिला था और न ही वे ठीक तरह से सो पाए थे।

‘सेवा’ द्वारा पंचायत की तरफ से सुमनबेन को कच्चे राशन की किट दिलवाई गई। उनकी बहू को पंचायत से 1000 मास्क तैयार करने का ऑर्डर भी दिलवाया गया।

उनके पति और बेटे दोनों को मनरेगा में काम दिलवाया गया परन्तु उनके परिवार की गुजर-बसर के लिए ये पर्याप्त नहीं है। इन लोगों के पास कोई और काम नहीं है। सुमनबेन के पति और बेटे दोनों का कहना है कि जब तक परिस्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगी वे अपने गाँव में ही काम करेंगे। कम-से-कम परिवार के साथ तो रह पाएँगे। बाहर तो किसी ने भी कोई मदद नहीं की, सरकारी इंतजाम भी नाकाफी ही थे इसलिए अब वे काम के लिए बाहर नहीं जाएँगे।

-कविता मालवीय
स्टेट प्रोग्राम को-ऑर्डिनेटर

सरकारी जमीन पर कंचन देवी की झोंपड़ी के चारों ओर केवल गंदगी नज़र आती है। इसलिए उस जगह का नाम कचरा टोला ही पड़ गया है। शौच के लिए भी उन्हें बाहर जाना होता है। चौथी कक्षा तक पढ़ी कंचनबेन के पाँच बच्चे हैं। वे घरेलू कामगार हैं और पति रिक़शा चालक हैं लेकिन वे जो भी कमाते हैं उसकी शराब पी जाते हैं। वे कहती हैं कि, ‘दीदी, हम तो जैसे नर्क में जीते हैं। तिस पर कोरोना के कारण मेरा काम भी छूट गया। काम बंद होने के कारण एक रात पति ने सिलेंडर ही बेच दिया ताकि शराब पी सके। जब तक पैसा पास में था वह घर लौटकर नहीं आया। बाहर ही शराब पीता रहा, जहाँ मुफ्त में खाना बंटता वहीं जाकर खा आता। घर की कोई सुध नहीं ली। ये भी नहीं सोचा कि बाढ़ के पानी में हम लकड़ी चुनने कहाँ जाएँगे और कैसे अपने बच्चों का पेट भरेंगे?’ इन कंचनबेन को भी कोरोना हो गया तब वार्ड पार्षद लखन पासवान ने फोन करके पुलिस द्वारा उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा। उनकी खबर सुनते ही ‘सेवा’ की कार्यकर्ताएँ पहले उनके घर गईं। फिर सेंटर जाकर कंचन बेन से जानकारी ली गई कि उनको समय पर खाना-दवाई-पानी मिल रहा कि नहीं। उनके घर राशन किट पहुँचाई गई। वार्ड पार्षद से मिलकर उनके बच्चों को राहत राशि दिलवाई ताकि वे भूखे न रहें। अब कंचनबेन ठीक होकर वापस आ गई हैं लेकिन उनके मालिक ने उन्हें काम से निकाल दिया है। अब वे कोशिश कर रही हैं कि उनको दूसरी जगह काम मिल जाए।

- अंजना बेन, ‘सेवा’ कटिहार

यह समय किसी को भी दोषी ठहराने का नहीं है

विश्व भर में फैली महामारी के बीच घरेलू कामगार पूरी दुनिया में चरम स्थिति पर हैं। इस खतरनाक महामारी से लगभग 60 लाख लोग पीड़ित हैं और लगभग 4 लाख लोग मारे गए हैं। भारत में लोगों ने देखा है कि कोविड-19 लॉकडाउन का प्रभाव विशेष रूप से श्रमिकों पर ज्यादा भारी पड़ा है। इनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं और **प्रवासी श्रमिक - जो अब तक अदृश्य बने हुए थे, वे अचानक से सबकी नज़रों में आए।** सरकारों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए श्रम कानूनों में ढील दी, और नियोक्ताओं को श्रमिकों का और अधिक शोषण के लिए उजागर किया। 'सेवा' संघ ने अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियन के साथ 22 मई को एक प्रदर्शन आयोजित किया जो श्रमिकों पर इस हमले के खिलाफ था।

हमने अपने काम से यह अनुभव किया है कि आम तौर पर घरेलू कामगारों को उनके काम की प्रकृति की वजह से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की चर्चा से भी बाहर रखा जाता है, क्योंकि उनका कार्यस्थल दूसरे का घर है। अगर गौर किया जाए तो घरेलू कामगार भी आवश्यक कार्यकर्ता हैं- खासकर जब वे बच्चों, बूढ़ों और बीमार लोगों की देखभाल करते हैं।

ये सभी घरेलू कामगार काम पर नहीं जा सके क्योंकि सार्वजनिक परिवहन का साधन उपलब्ध नहीं था। अधिकांश कामगार लॉकडाउन के बाद से काम पर नहीं जा सके, यानि लगभग 60 दिन तक उनके पास काम नहीं था। नियोक्ताओं को अलग-अलग माध्यम से वेतन देने का अनुरोध किया गया था, फिर भी कई श्रमिकों को भुगतान नहीं किया गया और वे हताश हो गए थे। **राष्ट्रीय घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल द्वारा एक अध्ययन ने खुलासा किया कि 85% से अधिक घरेलू श्रमिकों को उनकी मजदूरी नहीं मिली है, और कई नियोक्ताओं ने मजदूरी का भुगतान करने के उनके अनुरोध को ठुकरा दिया है।** 'सेवा' के ऑर्गनाइजर और आगेवान कई राज्यों में आपातकालीन राहत प्रदान करने, खाद्य किट वितरित करने और उन्हें सामुदायिक रसोईघर

से जोड़ने के कार्य में शामिल हो गए। कई श्रमिकों को केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा घोषित राशन की सुविधा प्राप्त हुई। कुछ राज्यों में उन्हें वेलफेयर बोर्ड का समर्थन मिला है।

अब जब हम अनलॉक के नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह उम्मीद की जाती है कि अधिक आराम होगा और काफी पाबंदियाँ भी हटा दी जाएँगी। साथ ही साथ लोगों को अपनी आजीविका संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाने की अनुमति भी दी जायेगी। लेकिन अब मध्यम वर्ग की महिलाएँ घर से काम कर रही हैं, तो इसी के चलते कई नियोक्ताओं ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें घरेलू कामगार महिलाओं की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, उन्हें संदेह भी है कि घरेलू कामगार वायरस के वाहक हैं। इसके विपरीत हमारे पास ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहाँ नियोक्ताओं द्वारा बीमारी फैलाने के मामले घरेलू कामगारों ने दर्ज कराए हैं। यह समय किसी को भी दोषी ठहराने का नहीं है।

इस वायरस की प्रकृति के कारण और हमारे भारत के अपने सामाजिक संदर्भ के कारण, यह महामारी गरीबों में ज्यादा फैल रही है, और हर रोज मामले बढ़ रहे हैं। गरीबों और निचले तबके के लोगों को सुरक्षा और सुरक्षा के सभी विशेषाधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यह समय है कि हम सभी को साथ में खड़ा होना है और इस निर्मम महामारी के खिलाफ लड़ना है। अब समय आ गया है कि आस-पास की स्थितियों के लिए जिम्मेदार होने के साथ ही श्रमिकों के अधिकार पर जोर देना है।

घरेलू कामगारों को इस बीमारी और इसके बारे में उचित जानकारी दी जानी चाहिए। इसी के साथ उचित सावधानी और निम्नलिखित सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण हैं। वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही साथ हमारे काम के अधिकार को भी संरक्षित करना होगा। सदस्यों के अपने आवासीय क्षेत्रों में घरेलू श्रमिकों के साथ जागरूकता सत्र कोविड-19 के पहलुओं और श्रमिकों के

अधिकारों की जानकारी देने संबंधित आयोजित किया गया। कई घरेलू कामगार सदस्य प्रवासी मजदूर भी हैं, और हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे सदस्यों के हक एक प्रवासी कामगार के हैं, और इसके लिए हमें सरकार से माँग करते हुए अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाना है।

अब जबकि लॉकडाउन के नियमों में ढील दे दी गई है, तब हमें यह बात अपने सदस्यों तक पहुँचानी है कि

वे अब पहले से ज़्यादा सावधानी बरत कर काम पर जाएँ। और इस बात का भी ध्यान दें कि महामारी अभी भी फैल रही है, खतरा अभी भी है, और अब हमें एक नए ढंग से रहने और काम करने के तरीकों को ढूँढना होगा, और उसी हिसाब से चलना भी होगा।

-अदिति याजनिक,
असिस्टेंट कॉ-ऑर्डिनेटर, आर्गनाइजिंग

हालात अब पहले जैसे नहीं रहे

‘सेवा’ ज़्यादातर घरखाता कामगार, घरेलू कामगार और निर्माणकाम करनेवाली बहनों के साथ वर्ष 2016 से पंजाब में कार्य कर रही है।

कोरोना वायरस की महामारी के समय हमारी बहनों को बहुत परेशानी हुई क्योंकि उनके पास कोई भी काम नहीं था। न केवल काम, बल्कि रोज़गार का साधन न होने की वजह से उनके पास खाने-पीने और जीवन जीने के लिए ज़रूरी वस्तुओं को खरीदने तक के पैसे नहीं थे।

ऐसे में ‘सेवा’ की ओर से पंजाब की 1800 बहनों के परिवारों को राशन देकर उनकी सहायता की गई।

जब मई के महीने से लॉकडाउन में राहत दिया जाना शुरू हुआ तब से कुछ घरेलू कामगार बहनों को काम पर वापस बुलाया जाने लगा है। हालाँकि **कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना के डर से लोग घरेलू कामगार बहनों को काम पर वापस नहीं बुला रहे हैं और ये बहनें इंतज़ार कर रही हैं कि कब वे अपने काम पर वापस जा पाएँ।**

इस दौरान घरेलू कामगार बहनों की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर रही। पहले जहाँ वे तीन-चार घरों में काम करती थीं वहीं अब इनके पास एकाध काम ही रह गया है। कई बहनों को काम के लिए काफी दूर जाना पड़ता है लेकिन आवागमन के साधनों की समस्या के चलते अब वे अपने घर से बहुत जल्दी निकलती हैं और पैदल ही काम पर जाती हैं। रोज़ आने-जाने का किराया खर्च करना उनके लिए संभव नहीं है लेकिन इसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत

घरेलू कामगार बहनों को है क्योंकि उनकी आमदनी और सेहत दोनों ही खतरे में हैं। फिलहाल सरकार की ओर से भी इन कामगारों के लिए किसी भी तरह की मदद की घोषणा नहीं की गई है।

घर में बैठकर सिलाई काम करने वाली बहनों में से अधिकतर तो बेरोज़गार ही बैठी हैं। उनमें से कुछेक को उनके कांटेक्टर से थोड़ा-बहुत काम मिलना शुरू हुआ है।

इस मुश्किल **महामारी के समय में ‘सेवा’ ने बढ़-चढ़कर अपनी बहनों की मदद की। राशन के अलावा कई घरखाता कामगार बहनों को ‘सेवा’ की ओर से मास्क बनाने का काम दिया गया ताकि किसी तरह उनकी रोज़ी-रोटी चलती रहे। हालाँकि अब कई घरखाता कामगार बहनों के पास आय के साधन हैं।** लेकिन इतना ही काफी नहीं है इन बहनों को काम मिलते रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ‘सेवा’ लगातार प्रयत्न कर रही है कि इन बहनों को नियमित रूप से काम मिलता रहे।

पंजाब में जो दिहाड़ी मजदूर थे वे काम न होने की वजह से अपने गाँव चले गए। जो रह गए हैं, उनका काम फिर से शुरू हुआ है पर हालात पहले जैसे नहीं हैं। कई मजदूर बहनों को आवश्यक कागजात के अभाव में सरकारी सुविधाएँ नहीं मिल पाईं। वर्तमान में ‘सेवा’ ऐसी बहनों के कागज़ तैयार करवाने में उनकी मदद की रही है ताकि उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके।

-तृप्ति शर्मा
डिस्ट्रीक्ट को-ऑर्डिनेटर, मोहाली

काम तो मिल रहा है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है

लाँ कडाउन के बाद से अब तक कई घरेलू श्रमिकों ने अपनी नौकरी गंवा दी है और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें उनके नियोक्ताओं ने पहले की पगार भी नहीं दी जिन दिनों में इन श्रमिकों ने उनके घर में काम किया था। यह दोष भी इन श्रमिकों के माथे पर ही रख दिया गया कि ये लोग वायरस के वाहक होते हैं। हालाँकि कई बार यह देखा गया है कि नियोक्ताओं के द्वारा इन कामगारों तक ये वायरस गया है।

ऐसी गलत भ्रांतियों को दूर करने और इन श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से 'सेवा' ने इन घरेलू श्रमिकों के बीच स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधित जागरूकता सत्र आयोजित किये।

15 जून को 'सेवा' ने 'माय फेयर होम अभियान' आयोजित किया। उस दिन 'सेवा' सदस्यों ने 5 नियोक्ताओं के घरों का दौरा किया। इस दौरे का परिणाम यह रहा कि कुछ नियोक्ता घर पर ही मिले और उन्होंने श्रमिकों को मजदूरी दे दी। कुछ नियोक्ता उस समय अपने घर में नहीं थे।

'घरेलू श्रमिक दिवस' पर 16 जून को, 'सेवा' द्वारा एक क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चलाया। 'सेवा' सदस्यों ने हस्ताक्षर एकत्र किए और एलसी को 700 हस्ताक्षर के साथ पत्र प्रस्तुत किया। **एलसी ने 'सेवा' टीम को बधाई दी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे एसएसवाय योजना के संबंध में किसी भी तरह की समस्या आने पर उसके निराकरण में पूरी मदद करेंगे।**

नियोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 'सेवा' के सदस्यों ने समाचार पत्रों और 'माय फेयर होम अभियान' के माध्यम से 2000 पत्रक वितरित किए। कुछ घरेलू श्रमिकों के पास फोन आए और उन्होंने इस काम की सराहना की।

रूपा हाजरा घरेलू कामगार हैं और अपने पति व तीन बच्चों के साथ बेरहामपुर में रहती हैं। लॉकडाउन के बाद से उनका काम बंद हो गया। उनके पति एक वैन रिक्शा

चालक हैं। जैसे-तैसे उनके घर का गुजारा चलता है। रूपा को मार्च से उसका वेतन नहीं मिला था। **माय फेयर होम कैम्पेन के दौरान रूपा हाजरा ने अपने नियोक्ता से बात की और उनको फिर से नौकरी देने के लिए मना भी लिया। हालाँकि उसके नियोक्ता ने उसे दो महीने के बजाय एक महीने का ही वेतन दिया।**

बीड़ी श्रमिक:

पिछले कुछ माह में बीड़ी बनाने वाले श्रमिकों का काम भी पूरी तरह से प्रभावित रहा। बीड़ी का व्यापार और बिक्री पूरी तरह से रुक से गए हैं। इसके अलावा, इनमें से अधिकतर घरों के कोई न कोई सदस्य प्रवासी मजदूर के रूप में किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। इन प्रवासी मजदूरों की पगार कई परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन लॉकडाउन के कारण, इन प्रवासी कामगारों में से अधिकतर का काम बंद हो गया। वे कई दिनों तक वहीं फँसे रह गए और उसके बाद जैसे-तैसे अपने-अपने घरों में वापस लौटे, खाली हाथ और परेशान।

राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि बीड़ी बनाने का काम तब तक जारी रह सकता है जब तक कि लोग अपने-अपने घरों में बैठकर इसे करें न कि समूहों में बैठकर। लेकिन इसके बाद भी इन परिवारों के लिए अभी भी स्थिति कठिन ही है। बीड़ी के लिए कच्चा माल अन्य राज्यों से प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा, इन परिवारों के पास आय का कोई अन्य स्रोत न होने के कारण वे परेशान हैं। सरकार चावल और गेहूँ का वितरण तो कर रही है लेकिन पूरे परिवार का पेट पालने के लिए ये पर्याप्त नहीं है।

अब बीड़ी मजदूरों को काम तो मिल रहा है लेकिन उन्हें न्यूनतम मजदूरी के बजाय कम मजदूरी मिल रही है।

- मोमिताबेन,
स्टेट को-ऑर्डिनेटर

सम्मान से रोजी कमाने का अवसर मिला

‘मेरा नाम सलमा है। लॉकडाउन में मैं बहुत परेशान थी। हमारा रोजगार खत्म हो गया। पहले जो काम किया था उसका पैसा भी ठेकेदार ने नहीं दिया। मैं सिलाई का काम करती हूँ। मेरे पति भी सिलाई करते हैं। हम दोनों का काम एक साथ ही बंद हो गया तो घर चलाने में बहुत दिक्कत होने लगी। पुराना काम तो छूट ही गया नया कोई काम नहीं मिल पा रहा था। उस समय मुझे मेहरून्निसाबेन से पता चला कि ‘सेवा’ संस्था बहनों से मास्क बनवाने का काम कर रही है। मैंने उनके ऑफिस जाकर कहा कि मुझे भी मास्क बनाने का काम दे दीजिए मैं बहुत दिक्कत में हूँ। उन्होंने मुझे भी काम दे दिया। मैंने मास्क बनाना शुरू किया और थोड़े ही समय में मैं हर दिन 100 मास्क तक बनाने लगी। हर पंद्रह दिन में इसकी मजदूरी भी मिलने लगी। इतना ही नहीं, मास्क सिलने में मैं प्रथम स्थान पर रही तो मुझे ‘सेवा’ से 500 रुपये का अतिरिक्त पुरस्कार भी मिला। हर पंद्रह दिन में पैसे मिल जाते हैं तो मेरे घर में खाने-पीने की दिक्कत खत्म हो गई।

मेरे जैसी कई बहनों को ‘सेवा’ ने सम्मान से रोजी कमाने का अवसर दिया, इसके लिए हम सब ‘सेवा’ के बहुत आभारी हैं।



कोविड-19 की महामारी ने दुनिया के हर देश को चेतावनी-सी दे डाली है। इसने हर छोटे-बड़े शहरों में रहने वाले अमीर हों या गरीब, सबको अपनी चपेट में ले लिया है।

जयपुर में बहनों के हालात बहुत खराब हो गए। पिछले कुछ दिनों से सभी तरह के

कार्य करने वाली बहनों के पास न तो दो वक्त की रोटी है, न आय का जरिया और न ही मदद की कोई उम्मीद। न उनके पास राशन है और न ही उनके पास पैसे हैं। आगे भी रोजगार मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

हालाँकि इस विकट स्थिति में सरकार ने बहुत मदद भी की लेकिन वह मदद इनकी जरूरतों के मुकाबले कम साबित हुई। जहाँ ये बहनें पहले काम करती थीं वहाँ के ठेकेदार ने भी इन बहनों के काम का शेष रह गया पैसा देने से इंकार कर दिया। ये मानो कुछ कम था कि मकान मालिकों ने भी मकान खाली करने को कह दिया।

‘सेवा’ राजस्थान द्वारा बहनों से मास्क बनवाने का काम अप्रैल माह के अंत में ही शुरू कर दिया गया था। इसके लिए बहनों को 3-4 दिन तक मास्क बनाने की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद सभी बहनें ठीक तरह से मास्क बनाने लगीं। इस काम से लगभग 64 बहनों को रोजगार मिला। सभी बहनों को रोज काम दिया जाता और वे दूसरे दिन मास्क बनाकर ऑफिस में जमा कर देतीं। इस तरह हर दिन बहनें लगभग 2000 मास्क ऑफिस में जमा करवातीं। सभी बहनें खुश थीं कि उनके पास अब काम था। उन सभी के घर में चूल्हे जलने लगे, राशन आने लगा। इस तरह बहनों ने 30,000 मास्क का पहला ऑर्डर पूरा कर दिया और सभी बहनों को प्रति मास्क 9 रुपये के हिसाब मजदूरी का भुगतान किया गया।

सबसे ज्यादा मास्क सिलने वाली बहनों को बोनस भी दिया गया। इससे हमारी सभी बहनों का उत्साह बढ़ा। सलमाबेन, फूलबेन, परवीन बेन, इन सबने महीने में पाँच से छह हजार रुपये तक कमाए। मास्क सिलने का यह काम 5 जून तक चला। इसके बाद 30,000 मास्क बनाने का एक और ऑर्डर मिला। इसका डिजाइन थोड़ा अलग है इसलिए बहनों को प्रति मास्क 4 रुपये सिलाई दी जा रही है। मुसीबत की घड़ी में बहनों को छोटा ही सही लेकिन उचित रोजगार तो मिला है।

कुछ इसी तरह की कहानी पापड़ बनाने वाली बहनों

की भी है। भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले काफी श्रमिक हैं इनमें से ही एक पापड़ बनाने वाली बहनें भी हैं। बीकानेर में हमारी 'सेवा' की लगभग 90 प्रतिशत बहनें पापड़ श्रमिक हैं।

इन बहनों का रोजगार भी लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से ठप्प हो गया। उनके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन न होने के कारण उनकी स्थिति बहुत ही कठिन हो गई। लगभग दो महीने बाद इस स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ क्योंकि जिन क्षेत्रों में कोरोना का कम प्रभाव है वहाँ पापड़ बनाने का काम फिर से शुरू हुआ है।

रामपुरा बस्ती में रहनेवाली बहनें जो पहले दिन भर में 1500 पापड़ बनाती थीं उन्हें अब दिन भर में मुश्किल से 100 से 600 पापड़ ही बेलने के लिए मिल पाते हैं। लेकिन पिछले दिनों कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ने के

कारण यह काम दोबारा से बंद हो गया। इन जरूरतमंद बहनों तक 'सेवा' बीकानेर की आशाबेन, रेणु बेन, दीपशिखा बेन ने आगेवान बहनों की मदद से सरकार की ओर से मिलने वाला पका खाना पहुँचाया।

आगेवान बहनों की सहायता से बस्ती की बहनों में सेनिटरी पेड का वितरण भी किया गया। इसके अलावा शासन की ओर से वितरित किये जाने वाले राशन को भी जरूरतमंद बहनों तक पहुँचाने में मदद की।

'सेवा' बीकानेर द्वारा 30 बहनों को मास्क बनाने का काम दिया गया। अभी त्यौहारों के समय इन बहनों को काम मिलने की आशा है। 'सेवा' भी प्रयास कर रही है कि इन बहनों को ज्यादा से ज्यादा काम मिल पाए।

- कविता बेन,
स्टेट को-ऑर्डिनेटर

बहनों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा

अ पनी सदस्य बहनों के जीवन को फिर से पूर्ववत करने का प्रयत्न 'सेवा' निरंतर कर रही है। 'सेवा' द्वारा हर क्षेत्र में कैंप लगाए गए। इन कैंप में यह सुनिश्चित किया गया कि हर बहन के पास श्रमिक लेबर कार्ड है। इसके अलावा सभी बहनों के स्वास्थ्य की जाँच भी करवाई गई। इन बहनों को नई-नई सरकारी योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है इसलिए वे इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पातीं। इस सभी बहनों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया।

श्रमिक कामगार बहनों को लेबर कार्ड के द्वारा अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाने का अवसर मिला। **हमारी सदस्य बहन रश्मि मिंज बहुत खुश हैं कि उनके बच्चे अब सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं।** इसके अलावा कई कामगार भाई-बहनों को शर्ट पेंट योजना का लाभ भी मिला। इसके अलावा, लक्ष्मी देवी, ललिता देवी आदि को प्रसूति योजना के तहत 15-15 हजार रुपये दिलवाए गए।

घरेलू कामगार बहनों को 'सेवा' द्वारा उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है। ये बहनें कम पैसों में भी काम करती हैं, कई बार तो इनसे अतिरिक्त काम करवा लिया जाता है लेकिन उसके लिए अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जाता। उन्हें लगता है कि वे कुछ बोलेंगी तो उनका काम छूट जाएगा।

उनकी चुप्पी को तोड़ने के लिए सेवा ने माई फेयर होम अभियान के तहत इन बहनों को उनके अधिकारों की जानकारी दी। उनसे कहा कि आपको अपने हक के लिए अपने नियोक्ता से सीधे ही बात करनी चाहिए। इसके अलावा, घरेलू कामगार बहनों की एक रैली भी निकाली गई। इस रैली में बहनों ने जो बैनर थाम रखे थे उसमें उन्होंने अपनी माँगों को लिखा था।

'सेवा' अपनी सदस्य बहनों के जीवन को सुधारने के लिए लगातार काम करती आ रही है। उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभ दिलवाया जाता है।

-रितु टिरकी
फिल्ड मोबिलाइजर

हमारी कोशिश है कि सभी बहनों को काम मिल पाए

‘सेवा’ उत्तराखंड में तीन तरह के ट्रेड के साथ काम कर रही है। यहाँ फिलहाल सभी तरह के कामगार परेशान हैं क्योंकि इन लोगों के पास या तो काम ही नहीं है या बहुत कम काम है। हमारे शहरी क्षेत्रों में बहनें घरखाता कामगार हैं। वे घर पर ही अलग-अलग तरह के काम करती हैं। कोविड के चलते इन सभी बहनों का काम खत्म हो चुका है।

हमारी ये सदस्य बहनें कम्प्यूटर के पार्ट बनाना, गत्ते बनाना, बुनाई के अलग-अलग सेंपल बनाना, लिफाफे बनाना, बल्ब की तार काटना, सामान पैक करना आदि कामों में संलग्न हैं। इन सभी बहनों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

ये सभी बहनें इन दिनों रोजगार की तलाश कर रही हैं। बाजार में मंदी के कारण सभी बहनों को काम नहीं मिल पा रहा है। अब बहनें परेशान होकर ‘सेवा’ के आफिस के चक्कर काट रही हैं कि हमें काम दिलवाने में मदद करें।

बहनों की स्थिति को देखते हुए हमने उद्योग निदेशालय और नगर निगम की योजनाओं के बारे में बहनों को बताना शुरू कर दिया है। इन बहनों को फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। **उद्योग निदेशालय में बहनों द्वारा बनाए गए सॉफ्ट टॉयस, कढ़ाई द्वारा बनाए गए कुशन कवर आदि दिखाए गए हैं। वहाँ के अधिकारियों को बहनों का काम बहुत पसंद आया है।** उन्होंने आश्वासन

उद्योग निदेशालय में बहनों द्वारा बनाए गए सॉफ्ट टॉयस, कढ़ाई द्वारा बनाए गए कुशन कवर आदि दिखाए गए हैं। वहाँ के अधिकारियों को बहनों का काम बहुत पसंद आया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे ट्रेनिंग के द्वारा इन बहनों को सरकारी हैंडी क्राफ्ट के तहत जोड़ लेंगे और इन्हें ऑर्डर भी देंगे।

दिया है कि वे ट्रेनिंग के द्वारा इन बहनों को सरकारी हैंडी क्राफ्ट के तहत जोड़ लेंगे और इन्हें ऑर्डर भी देंगे। हमने बहनों की लिस्ट बनाकर उद्योग निदेशालय को दे दी है।

कुछ बहनें पापड़-बड़ी बनाती हैं वे भी अभी बाजार की तलाश कर रही हैं।

दूसरे, हम घरेलू कामगारों के साथ काम करते हैं। इन कामगारों को भी कोविड के चलते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ गया है। जो बहनें पहले 4 से 5 घरों में काम करने जाती थीं वे अब 1 से 2 घरों में ही काम कर रही हैं। कुछ लोगों ने घर में काम करने वाली बहनों को हटा दिया है, कुछ का काम लोकल ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण काम छूट गया है। इन सभी बहनों के पति भी मजदूरी करते हैं और अभी उन लोगों के पास भी काम नहीं है। पहले वे हफ्ते में 5 से 6 दिन काम करते थे पर अब 1-2 दिन ही काम मिल पा रहा है। जो लोग अपने राज्य लौटे हैं वहाँ पर भी उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। बिहार में खेत मजदूरी का काम भी सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। फैक्ट्रियों में भी छंटनी चल रही है। लोग नये काम की तलाश में हैं।

तीसरे, हम कृषि वाली बहनों के साथ काम करते हैं। आजकल ये बहनें काम कर पा रही हैं क्योंकि ये बहनें अपने ही खेतों में काम करती हैं। बहुत कम बहनें खेत मजदूरी करती हैं। बहनों को सरकार द्वारा बीज, खाद दिलवाए जा रहे हैं, मंडियों तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। जो लोग बाहर नौकरी करते थे वे सब उत्तराखंड लौट आए हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपनी बहनों को वापस रोजगार से जोड़ पाएँ। अभी इन बहनों को मनरेगा का काम भी मिलना शुरू हो गया है।

- रीना,
डिस्ट्रीक्ट को-ऑर्डिनेटर

सदस्य बहनों को रोजगार सुलभ कराया

उत्तराखंड में 'सेवा' से लगभग 25 हजार बहनें जुड़ी हुई हैं जिसमें से लगभग 8 हजार बहनों के पति, भाई, पिता अपना घर-गाँव छोड़कर बाहर जैसे मुम्बई, देहरादून, दिल्ली, पूना, अहमदाबाद आदि राज्यों में कंपनी या होटलों में काम कर रहे थे। गाँव में खेती-बाड़ी को जंगली जानवर हर बार उजाड़ देते हैं जिसकी वजह से सारी मेहनत और लागत व्यर्थ हो जाती है। ये लोग काम की तलाश में अपना गाँव छोड़कर बाहर चले गये तथा जैसे-तैसे अपने परिवार का निर्वाह कर रहे थे। किसी परिवार में उनकी माता, बहन या परिवार गाँव में रह रहा था। कई लोग ऐसे थे जो अपनी पत्नी और बच्चों को भी साथ ले गए थे और किराये के कमरों में रह रहे थे।

जब पूरे देश में इस महामारी ने जन्म लिया तो हर व्यक्ति की स्थिति में बदलाव आ गया। 22 मार्च 2020 को कोविड-19 के चलते पूरे भारत वर्ष में पूर्णतः लॉकडाउन घोषित कर दिया गया जिसके कारण ये सभी प्रवासी लोग वापस अपने-अपने घरों में आ गए। हालाँकि ये शुरूआती समय श्रमजीवी भाई-बहनों के लिए बहुत कठिनाई से भरा रहा क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था, पैसा नहीं था। जो लोग अपने परिवार को साथ ले गए थे उनके सामने तो घर की दिक्कत भी थी इसलिए वे वापस आकर अपने



घर की मरम्मत में लग गए।

मनरेगा का काम पूरी तरह से बंद था। खेत में नहीं जा पा रहे थे जिससे खेतों का रखरखाव पूर्णतः बंद हो गया था। हमारी 750 बहनें, जो हमसे को-ऑपरेटिव के तहत जुड़ी थीं, उनका रोजगार भी बंद हो गया। उनकी उगाई गई फसल खराब होने लगी। साथ ही, जो बहनें बाजार में जाकर अपने आलू, प्याज हल्दी, धनिया, मिर्च, सब्जियाँ बेच देती थीं वे घर पर रखे-रखे ही खराब होने लगे।

कृषि से जुड़कर 150 बहनें जो दूध का व्यवसाय करके अपना जीवन निर्वाह कर रही थीं, उनका काम भी बंद हो गया।

इन सब बहनों की मदद करने के उद्देश्य से 'सेवा' द्वारा को-ऑपरेटिव की बहनों से मई माह में 3 क्विंटल धनिया, 97 किलो हल्दी, 16 किलो मिर्च और 5 किलो मसूर आदि खरीदे गए।

दूध की डेरी में हमारी 150 बहनें जुड़ी थीं, उनके रोजगार को शुरू करने के लिए सरकार से बातचीत करके फिर से दूध का कार्य शुरू करवाया गया। हमारे श्रमिक भाई- बहनों के जॉब कार्ड बनवाए गए ताकि उनको मनरेगा के तहत काम मिल सके।

200 श्रमिकों के नये कार्ड बनवाकर दिए जिससे उनके खाते में 1000/-रुपये सरकार की ओर से जमा किये गए। 1600 बहन व भाईयों के जनधन खाते खुलवाकर लाभ दिलवाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा 2000 बहनों व भाइयों को लाभ दिलवाया गया। उन सभी के खाते में 2000/-रु. जमा किये गये हैं।

जनधन खाते से 1700 बहनों के खाते खोलकर 500 रु. सरकार द्वारा बहनों के खाते में पहुँचाये उसके बाद उनके खाते से यह राशि निकालकर सेवा सार्थक बी सी द्वारा बहनों तक पहुँचाई गई।

इसके अलावा 'सेवा' द्वारा 980 बहनों को सेनिटरी नेपकिन बाँटे गए। 100 बहनों को राशन तथा 1000 बहनों को मेडिकल किट दी गयी है।

हमारी सदस्य बहनों ने 2300 मास्क भी बनाए। इन मास्क के लिए प्रत्येक बहन को 10 रुपये प्रति मास्क की दर से भुगतान किया गया। इस काम से बहनों ने 2300 रुपये तक की कमाई की।

-बीनाबेन,
डिस्ट्रीक्ट को-ऑर्डिनेटर

आगेवान की कहानी, उनकी जुबानी

कोरोना महामारी ने कामगार लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गए लॉकडाउन के निर्णय ने सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों पर आर्थिक रूप से नकारात्मक परिणाम छोड़ा है।

इस महामारी ने कामगार बहनों के जीवन को किस तरह से प्रभावित किया, इसे और बेहतर तरीके से जानने के लिए हमने 'सेवा' की एक आगेवान बहन से बातचीत की और उनके काम में आ रही मुश्किलों को समझा। उन्होंने बताया कि,

'मेरा नाम वंदना है। मैं जहांगीरपुरी में रहती हूँ। 'सेवा' दिल्ली की आगेवान और 'सेवा' दिल्ली ट्रस्ट की कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। मैं एक वेंडर हूँ। रेहड़ी-पटरी पर बच्चों के खिलौने और आर्टीफिशियल ज्वैलरी बेचती हूँ। इस महामारी काल में मेरा काम पूरी तरह से बंद हो गया और मेरी आमदनी पर भी बहुत असर पड़ा। आने वाले समय में भी सही ढंग

से काम चल पाने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। मैं अपनी कमजोर होती आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थी। लेकिन जब मैंने अपने इलाके में रह रही अन्य बहनो की आर्थिक स्थिति को देखा तो मुझे अपनी तंगी छोटी नज़र



आने लगी लोग इतने परेशान थे कि उनके पास खाने तक के लिए राशन नहीं था। फिर मैंने उनकी मदद करने और उनको 'सेवा' से जोड़ने का सोचा और अपने समुदाय के लोगों को 'सेवा' से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। लॉकडाउन के समय सेवा शक्ति केंद्र पर राशन वितरण किया गया, मैंने जरूरतमंद लोगों को इस सुविधा से जोड़ा और लिस्ट बनाने से लेकर बांटने तक सारी प्रक्रिया में शामिल रही। दिल्ली सरकार द्वारा ई.कूपन से लोगों को जोड़ा ताकि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो लोग भी राशन प्राप्त कर सकें। 'सेवा' की कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क में रही और जहाँ भी जरूरत होती लोगों को फौरन राहत दी जाती। लोगों की मदद करके मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि महसूस हुई। इस महामारी काल में 'सेवा' ने अपने सदस्यों की अपने बच्चों की तरह देखभाल की है।

मेरा मानना है कि दूसरों की मदद करने और उनके काम आने के लिए 'सेवा' से अच्छा विकल्प और कोई नहीं हो सकता।

मालिक : "अनसूया ट्रस्ट" की ओर से प्रकाशक-मुद्रक : प्रीति शान्त, म.प्र.हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पी.एण्ड टी. चौराहा, शास्त्रीनगर, भोपाल (म.प्र.)-462003. फोन : 0755-2790039
मुद्रण : प्रियंका ऑफसेट, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल. फोन : 2555789

अनसूया

अनसूया कार्यालय :

द्वारा- म.प्र.हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
माथाराम सुरजन स्मृति भवन, पी.एण्ड टी. चौराहा,
शास्त्रीनगर, भोपाल (म.प्र.) 462003 फोन नं. : 2790039
ई-मेल - ansuya_trust@rediffmail.com,
website:www.sewabharat.org